

प्रेस सूचना ब्यूरो भारत सरकार

दिनांक : 14 भाद्रपद, 1928 शक
5 सितम्बर, 2006

प्रेस नोट

मैग्नेटिक मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रसार

मई, 1999 में स्थापित सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रसार संबंधी राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत, अब सांख्यिकीय आंकड़ों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोक्ताओं को मैग्नेटिक मीडिया पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय लंबे समय से राष्ट्रीय महत्व के वृहत् सांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्रित एवं संकलित कर रहा है। इन्हें अभी तक सामान्यतः मानक सारणियों वाली केवल रिपोर्टों के रूप में प्रसारित किया गया था। अब, प्रसार नीति के अपनाने से, मंत्रालय इस मंत्रालय के संगणक केन्द्र के माध्यम से प्रयोक्ताओं हेतु उपलब्ध सर्वेक्षणों एवं आर्थिक गणनाओं के माध्यम से एकत्रित वैधीकृत यूनिट-स्तर आंकड़े बना रहा है। प्रयोक्ताओं की निशुल्क एक्सेस हेतु मंत्रालय के सभी प्रकाशनों को मंत्रालय की वेबसाइट <http://mospi.nic.in> पर रखा गया है।

मैग्नेटिक मीडिया पर यूनिट-स्तर के आंकड़े

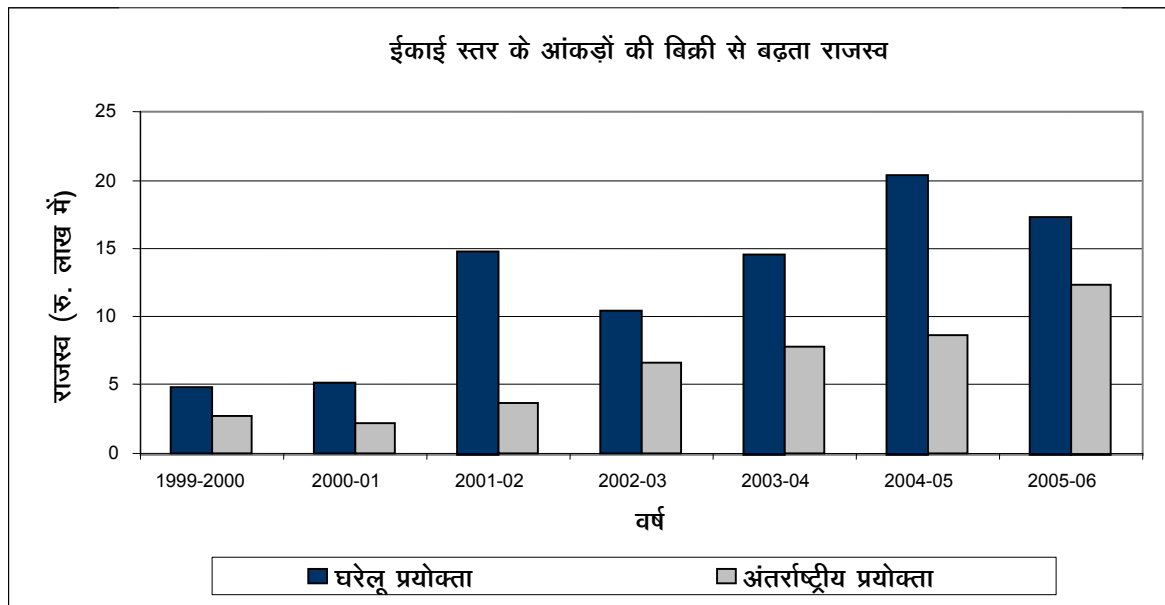
मंत्रालय का केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन(के.सां.सं.) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (रा.प्र.सर्वे.सं.) प्रत्येक वर्ष भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विविध आयामों पर व्यापक एवं अद्यतन सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित करता है। योजना और नीति निर्माण हेतु महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ, वैज्ञानिक रूप से आयोजित आर्थिक गणनाओं, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षणों और मूल्य संग्रहण सर्वेक्षणों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा एकत्रित आंकड़े-सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधानकर्ताओं के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। प्रसार नीति के अंतर्गत, वैधीकृत यूनिट-स्तर आंकड़े अर्थात् क्लीन्ड परसन-, परिवार-और प्रतिष्ठान-स्तर के आंकड़े उन पर आधारित प्रकाशित रिपोर्टों के जारी होने के बाद या क्षेत्र कार्य के तीन वर्ष पूरा होने के बाद, जो भी पहले हो, मांग पर अब प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। फिर भी, सर्वेक्षित इकाईयों की पहचान ब्यौरों को गोपनीय रखते हुए प्रयोक्ताओं को भुगतान पर यूनिट-स्तर आंकड़ों की आपूर्ति की जाती है।

रा.प्र.सर्वे.सं. प्रत्येक कृषीय वर्ष (जुलाई-जून) के दौरान एक वर्ष या छह माह तक चलने वाले दौर के एक या दो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित करता है। प्रत्येक दौर के लिए, सर्वेक्षण हेतु विषयों के एक समूह को लिया जाता है जो सामान्यतः प्रत्येक पांच या दस वर्षों के बाद दोहराया जाता है। मंत्रालय का संगणक केन्द्र प्रसार हेतु 42वें दौर से आयोजित किए गए सभी दौरों और 38वें दौर (1983) के यूनिट-

स्तर आंकड़ों को परिरक्षित रखता है। इन प्रत्येक दौरों में कवर किए गए विषयों और उनके मूल्यों सहित आंकड़ों की उपलब्धता का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इसी प्रकार, प्रयोक्ताओं को प्रसार करने के लिए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के कारखाना क्षेत्र संबंधी आंकड़े संगणक केन्द्र द्वारा परिरक्षित किए जाते हैं। 1974-75 से 1994-95 तक के वर्षों हेतु वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का आंकड़ा सार तथा 1996-97 से 2003-04 तक के विस्तृत आंकड़े उपलब्ध हैं। संगणक केन्द्र प्रसार हेतु पिछली दो अर्थात् 1990 तथा 1998 के दौरान आयोजित तीसरी तथा चौथी आर्थिक गणना के आंकड़े भी परिरक्षित करता है। सभी 59 केन्द्रों तथा समस्त भारत हेतु उप समूह, समूह तथा केन्द्र स्तर पर शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [सीपीआई(यूएनएमई)] भी उपलब्ध हैं। संगणक केन्द्र से इन आंकड़ों को प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा आंकड़ों के लिए अनुरोध करने हेतु अपेक्षित अंडरटेकिंग निष्पादित करने संबंधी प्रपत्र वेबसाइट पर डाला गया है।

वैयक्तिक पहचान को गोपनीय रखते हुए ये आंकड़े मंत्रालय की वेबसाइट पर दर्शाई गई दर सूची में उद्धृत मूल्यों के भुगतान करने पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयोक्ताओं दोनों को नियमित रूप से दिए जा रहे हैं।



इकाई-स्तर आंकड़ों की बढ़ती मांग

मई, 1999 में इकाई स्तर के आंकड़ा प्रसार की नीति अपनाने से प्रयोक्ताओं से उत्साहजनक उत्तर मिला। मार्च, 2000 के अंत तक प्रयोक्ताओं से आंकड़ों हेतु 58 अनुरोध प्राप्त हुए। अब, संगणक केन्द्र प्रतिवर्ष सौ प्रयोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है। कुल मिलाकर, जुलाई, 2006 तक संगणक केन्द्र ने 857

प्रयोक्ताओं को आंकड़े उपलब्ध करवाए हैं। स्पष्ट रूप से, जब से नीति प्रभावी हुई है, आंकड़ा बिक्री से प्राप्त राजस्व में वृद्धि हुई है। अब तक लगभग 1.44 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त हुआ है।

इस संदर्भ में भारत की पहल का अंतर्राष्ट्रीय प्रयोक्ताओं ने स्वागत किया है। अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू प्रयोक्ताओं को आंकड़ों की बिक्री से मंत्रालय द्वारा अर्जित राजस्व में समान तीव्र दर से वृद्धि हुई है। सामाजार्थिक सर्वेक्षणों के इकाई-स्तर के आंकड़ों की प्रयोक्ताओं की तरफ से अधिक मांग है। लगभग तीन चौथाई अनुरोध सामाजार्थिक सर्वेक्षणों के आंकड़ों के लिए किए गए हैं। शेष अनुरोध अधिकांश वा.उ.सर्वे. संबंधी आंकड़ों के लिए है।

वेबसाइट पर रिपोर्टें/प्रकाशन

मंत्रालय सर्वेक्षणों के आधार पर रिपोर्टों के रूप में अनेक प्रकाशनों एवं गौण आंकड़ों के आधार पर अन्य प्रकाशनों का प्रकाशन करता है। पहले केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के संबद्ध विभागों के चुनिंदा प्रयोक्ताओं को इन प्रकाशनों की सिर्फ हार्ड कॉपी निःशुल्क दी जाती थीं। प्रकाशनों की सिफ कुछ ही प्रतियां बिक्री हेतु उपलब्ध होती थीं।

सितंबर, 2004 से मंत्रालय की समस्त प्रकाशित रिपोर्टें प्रयोक्ताओं के लिए व्यापक प्रसार हेतु मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। संगणक केन्द्र द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित वेबसाइट पर न सिर्फ वर्तमान रिपोर्टें बल्कि पहले की रिपोर्टें भी इलेक्ट्रॉनिक फार्म में उपलब्ध हैं। संगणक केन्द्र ने प्रयोक्ताओं के लिए ऑन लाइन पंजीकरण हेतु पंजीकरण फार्म भी तैयार किया है जिससे प्रयोक्ता की पूरी पहचान हो जाती है।

पंजीकृत प्रयोक्ताओं तथा रिपोर्ट देखने वालों की संख्या

जुलाई, 2006 को समाप्त बाईस महीनों के दौरान रिपोर्टें/प्रकाशनों के ऑन लाइन एक्सेस/देखना/डाउनलोड हेतु पंजीकृत प्रयोक्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 16267 प्रयोक्ताओं ने ऑन लाइन पंजीकरण कर वेबसाइट पर मंत्रालय के प्रकाशनों का अध्ययन किया है। औसतन लगभग 740 प्रयोक्ता प्रत्येक माह रिपोर्टें/प्रकाशनों का अध्ययन करते हैं। हालांकि आरंभ में रिपोर्टें का अध्ययन करने वाले प्रयोक्ताओं की संख्या कम थी परंतु अब यह प्रति माह लगभग 1000 प्रयोक्ता के स्तर तक पहुंच गई है।

कुल प्रयोक्ताओं में से 73% भारतीय तथा लगभग 27% विदेशी थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रयोक्ताओं में से दो-तिहाई से अधिक संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चीन, जापान, कनाडा तथा फ्रांस के थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रयोक्ताओं में से एक-तिहाई से अधिक तो संयुक्त राज्य और यू.के. के ही थे। जुलाई, 2006 में समाप्त बाईस महीनों के दौरान 16,267 पंजीकृत प्रयोक्ताओं ने मंत्रालय की रिपोर्टें एवं प्रकाशनों का 73,443 बार हिट किया है।

अन्य पहल

प्रयोक्ताओं को बेहतर एक्सेस प्रदान करने के लिए संगणक केन्द्र अभी एक सक्रिय वेबसाइट तैयार कर रहा है। इसमें सरकारी आंकड़ों के आंकड़ा वेयरहाउस का सृजन शामिल है जो विशिष्ट आंकड़ा प्रयोक्ताओं तथा सामान्य प्रयोक्ताओं के लिए एक ही स्रोत से अपेक्षित प्रसंस्कृत रूप में प्रकाशित तथा अप्रकाशित आंकड़े आसानी से उपलब्ध करा पाएगा। वर्तमान समय में आंकड़ा वेयरहाउस के सृजन पर एक प्रायोगिक परियोजना चल रही है। वेयरहाउस को चरणों में बनाए जाने की योजना है। वर्तमान समय में रा.प्र.सर्वे.सं., सीपीआई (यूएनएमई) के 'परिवार उपभोक्ता व्यय' तथा 'रोजगार एवं बेरोजगारी' सर्वेक्षणों के आंकड़ों तथा पशुधन गणना पर वेयरहाउस बनाया जा रहा है। प्रस्तावित आंकड़ा वेयरहाउस की स्थापना न केवल विशिष्ट प्रयोक्ताओं की आंकड़ा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में बल्कि भारतीय लोगों के सामान्य हितों को पूरा करने में भी एक मजबूत कड़ी साबित होगी।